

Trine 231  
20/09/18

No. – Pen.Aut./order/K-85/2018-19/1119

Dated: 13/06/2018

To,  
The P.A.G. (A&E)  
A.P, Saifabad Road,  
Hyderabad – 500004.

Subject: - Regarding Interim Relief on Pension to retired officers of Rajasthan Judicial Service and family pensioners.  
Reference: - Order No. F10 (5)/Law/2018 dated 21.05.2018 of state Government law & legal matters dept.

Sir,

With reference to the subject cited above, it is to state that a copy of letter no. - P.5 (247) D.P.D./Rule/2018/Part-2/1707-1770 H dated – 30.05.2018 of Directorate, Pension and Pensioner's welfare department, Rajasthan, Jaipur and order no.- F 10 (5) Law/2018/ dated 21.05.2018 of law & legal matter department of state government is being forwarded.

Hence, you are requested to circulate it to all concerned / pension payment officers / Bank branches to make instructions for payment.

Your's faithfully

Sr. A.O. / Pension Authorization

Letter No. – PA/Order/2018-19

Dated: .....

Copy forwarded to the followings for information & necessary action –

1. Director, Pension & Pensioner's welfare department, Rajasthan, Jaipur
2. P.A.G. (E&RSA) Jaipur
3. Branch officer, T.M. Section.

Sr.A.O./Pension Authorization.

**Government of Rajasthan**  
**Directorate / Pension and Pensioner's Welfare Department**  
**Rajasthan, Jaipur**

S.No.-P-5 (247) /D.P.D./Rule/2018/Part -2/1707-1770 H

Dated – 30.05.2018

1. Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur
2. All Treasury Officers \_\_\_\_\_ Rajasthan.
3. All Banks authorized by Rajasthan Government for Pension dis bursion –

Subject: - Regarding Interim Relief on Pension / Family Pension to retired officers  
Of Rajasthan Judicial Service.

Sir,

With reference to the subject cited above, it is to state that orders have been issued vide order no. F 10 (5) law / 2018 dated 21.05.2018 of state government law and legal matters department to grant 30 percent Interim Relief Per month on basic pension / family pension to retired officers of Rajasthan Judicial Service from 01.01.2016 (copy enclosed). The arrangement for the payment of 30 percent Interim Relief on basic pension / family pension to retired officers of Judicial Service & family pensioners, may be made from 01.01.2016 on date of commencement of pension (whichever is later) as per the following conditions –

- 1) D.A. will not be paid on the above Interim Relief .
- 2) If the benefit has been provided to a retired judicial officer and family pensioner by fixing pension /family pension under Seventh pay as per order/ circular/notification dated 30.10.2017 or 09.12.2017 issued by finance department of state government, and Interim Relief has been given thereon, the above Interim Relief is to be adjusted out of the excess amount paid earlier by adjust pension/ family pension fixation which had been made earlier.
- 3) In compliance with Supreme Court orders, it is requested to calculate Interim relief from 01.01.2016 which is payable from June 2018 along with pension and arrears. This may be ensured.
- 4) A software may be developed for showing separately the payment of above Interim Relief. All bankers and treasuries are requested to show this payment of IR separately in their scroll along with date and period.
- 5) Regular payment of IR from June 2018 may be ensured and when pay scales are announced this IR may be adjusted.

Top priority may be given to this please.

Enclosed: - As above

Yours Faithfully

(Parmeshwari Choudhary)  
Director





157674696

44/6

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

रजिस्टर्ड-पत्र

①

संख्या / No..... पेंशन प्राधि./आदेश/के- 85/2018-19/ 1119

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date..... 13/6/18

श्रीमान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक),

मान्द्र जे. 1, सोफाकाड रोड,  
देवराबाद - 500004 -

21.05.18  
378/18  
23/6/18  
JUN 2018

विषय:- राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन व पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन पर अंतरिम राहत के भुगतान बाबत।

प्रसंग:- राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)/विधि/2018 दिनांक 21.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(247)निपेवि/नियम/2018/पार्ट-2/1707-1770 H दिनांक 30.05.2018 एवं राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)/विधि/2018 दिनांक 21.05.2018 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर भुगतान हेतु निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे।

सलंग:- ज्ञापन दिनांक 21.05.2018 की प्रति ②

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति  
दिनांक:-

क्रमांक:- पीए/आदेश/2018-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), जयपुर।
- (3) शाखाधिकारी, टी.एम. अनुभाग।

Transferred to PM-TS for n.a.

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन प्राधिकृति

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाष:(0141) 2385431-39, फैक्स:(0141)2385263

Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263

ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

718612



**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग**

**राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:—प05 (247)/निपेवि/नियम./2018/पार्ट-2/1707-1770H. दिनांक 30-05-2018

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी, \_\_\_\_\_, राजस्थान
3. पेंशन वितरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत समस्त बैंक

**विषय :- राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन व पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन पर अंतरिम राहत के भुगतान बाबत ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के विधि एवं विधिक मामलात विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (5)विधि/2018 दिनांक 21.05.2018 के द्वारा राजस्थान राज्य के न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर उनकी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रति माह दिनांक 01.01.2016 से देने हेतु निर्देश जारी किये हैं (प्रति संलग्न) । राज्य सरकार के उक्त आदेशों कि अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों व पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 30 प्रतिशत अंतरिम राहत मूल पेंशन/मूल पारिवारिक पेंशन का भुगतान **01.01.2016 से अथवा जिस दिवस से पेंशन प्रारम्भ हुई हो (जो भी बाद में हो से)** निम्नांकित शर्तों के अनुसार भुगतान करने की कार्यवाही करने की व्यवस्था करे:-

(1) उक्त अंतरिम राहत पर किसी भी प्रकार की मंहगाई राहत देय नहीं होगी ।

(2) अगर किसी भी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी व पारिवारिक पेंशनर्स को राज्य सरकार के वित्त विभाग(नियम) द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 या 9.12.2017 के अनुसार सातवे वेतनमान के अधीन कोई पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण कर लाभ दिया गया है व उस पर मंहगाई राहत दे दी गयी है, तो उक्त पूर्व में किये गये पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण को निरस्त कर पूर्व में किये गये अधिक भुगतान की राशि को उक्त अंतरिम राहत में से समायोजित किया जाना है ।

(3) उक्त अधिकारियों को दिनांक 01.01.2016 से अंतरिम राहत की गणना कर माह जून, 2018 में देय पेंशन के साथ बकाया मासिक अंतरिम राहत का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें । जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना हो सकें ।

(4) उक्त भुगतान की गयी अंतरिम राहत की राशि को दर्शाने हेतु न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के स्कॉल में उचित प्रावधान सॉफ्टवेयर में कर दिया गया हैं। सभी बैंकर्स व कोषालयों से अनुरोध है कि अंतरिम राहत के भुगतान की राशि को स्कॉल में अलग से दर्शाये व कितने समय की दी गयी है, उचित करें

(5) जून 2018 के बाद नियमित रूप से अग्रिम आदेशों तक न्यायिक अधिकारियों को अंतरिम राहत भुगतान सुनिश्चित किया जावे तथा भविष्य में जब भी सरकार के द्वारा न्यायिक अधिकारियों हेतु वेतनमान की घोषणा की जावेगी उसमें से अंतरिम राहत के रूप में किये गये भुगतान को समायोजित किया जाना है ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)  
निदेशक

कार्यालय महालेखाकार  
Office of the Accountant General  
प्राप्ति संख्या / Receipt  
01 JUN 2018  
राजस्थान, जयपुर  
Registration

दी-161  
06-06-18

पेशा  
5.6.18  
श्री कर्मा  
जून 18



Government of Rajasthan  
Law & Legal Affairs Department

R.No.10(5)/Law/2018

Jaipur, Dated 21 MAY 2018

ORDER

The Governor is pleased to order to implement the following recommendations of the Second National Judicial Pay Commission:-

- PA  
Q  
29.5.18
1. Interim relief to the extent of 30% of increase in basic pay with accrued increments shall be paid to all categories/ranks of Judicial Officers.
  2. The said increased in Pay shall be treated as a separate component and no D.A. is payable thereon.
  3. Arrears shall be worked out with effect from 01.01.2016 on the above basis. The details of calculations are set out in Annexure-I.
  4. On the same basis, the interim relief shall be provided to the pensioners and family pensioners with effect from 01.01.2016 and the arrears to be paid accordingly subject to the condition that if pension/family pension of judicial officers has been revised under FD Memorandum No. F.12(6)FD/Rules/2017 dated 30.10.2017 and 09.12.2017 that amount of increase in pension/family pension alongwith dearness relief thereon shall be adjusted against the amount of interim relief payable under this order.
  5. The amounts payable by way of interim relief under this order are liable to be adjusted against the future determination pursuant to the final report submitted by the Commission."

This order issues with the concurrence & Vetting of Finance(Rules) Department vide their I.D. No. 101802095 dated 30.04.2018 & 101802730 dated 21.05.2018 Respectively.

By order of the Governor.

sd.  
(Mahaveer Prasad Sharma)  
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action:-

1. Secretary to the Hon'ble Governor of Rajasthan.
2. Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.
3. P.P.S. to Chief Justice of Hon'ble High Court, Jodhpur.
4. P.S. to Hon'ble State Law Minister of Rajasthan.
5. P.S. to Hon'ble Chief Secretary, of Rajasthan.
6. Registrar General, Hon'ble High Court, Jodhpur/Jaipur Bench Jaipur.
7. P.S. to Principal Secretary, Law
8. Principal Accountant General, Rajasthan Jaipur.
9. Principal Accountant General(Audit), Rajasthan Jaipur.
10. P.S. to A.C.S. Finance (Rules/budget) of Rajasthan.
11. Director, Pension and Pension Welfare, Rajasthan, Jaipur.

sd.  
21.5.18  
Joint Secretary, Law

sd - 155  
21.5.18